उप्र में स्थापित होगा पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र

- सरकार और विश्व आर्थिक मंच की तरफ से कार्यशाला का आयोजन
- सार्वजनिक-निजी विनिर्माण केंद्र की स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में देश का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित होगा। इस संदर्भ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में यह केंद्र अहम भूमिका निभाएगा जिससे कि विनिर्माण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए नई तकनीक का आदान-प्रदान जरूरी है। इसकी स्थापना के बाद विभिन्न औद्योगिक समूहों द्वारा एक दूसरे को नई तकनीक के बारे में आसानी के साथ जानकारी दी जा सकेगी।

विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) और सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से शनिवार को पिकअप भवन में उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में उप्र की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था में बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच के साथ मेल खाती है। डब्लूईएफ के सेंटर फार एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन के ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी हेड कायराकोस त्रिअंटफिलिडिस ने कहा कि यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों, डिजिटलीकरण और नवाचार के लिए एक हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। डब्लूईएफ के सेंटर फार द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क की एशिया की प्रमुख वंदना मेनन ने विनिर्माण केंद्र के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ● फाइल

कार्यशाला में पीटीसी, मारुति सुजुकी, आदित्य बिड़ला समूह, ह्यवर, जेके सीमेंट, अशोक लीलैंड, ग्रीनलैम, हुंडई इंडिया, एचसीएल टेक्नोलाजी, आरएसीएल ग्रीनटेक लिमिटेड, भारतीयम बेवरेजेज सहित 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने उन्नत विनिर्माण केंद्र के साथ जुड़ने की सहमति भी दी। साथ ही उप्र में निवेश की संभावनाओं पर भी कार्यशाला में चर्चा की गई।